संख्या- 8/2024/89/003-53-2002-50-2019

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0, लखनऊ।
2.दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, आगरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराइच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 15 फरवरी, 2024**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति (अनुदान संख्या-16, जिला योजना-सामान्य)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक- 414/दुग्ध-4/नियो0/तकनीकी निवेश-सामान्य(283)/23-24, दिनांक 30 जनवरी, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-16(जिला योजना-सामान्य) में प्राविधानित धनराशि रू0 464.10 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-23/2023/478/001-53-2002-50-2019, दिनांक 07 जून, 2023 द्वारा रू0 77.35 लाख एवं द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-41/2023/1018/002-53-2002-50-2019, दिनांक 28 नवम्बर, 2023 द्वारा रू0 77.35 लाख की वित्तीय स्वीकृति, इस प्रकार कुल 154.70 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अवशेष धनराशि रू0 309.400 लाख में से प्रदेश के 75 जनपदों के लिए दवा (डिवर्मर, थनैला व टिक कन्ट्रोल), पी0सी0डी0एफ0 के पशुआहार निर्माणशालाओं द्वारा निर्मित मिनरल मिक्स्चर व पशु आहार के लिए क्रमशः 30:20:50 के अनुपात में व्यय किये जाने हेतु तृतीय किश्त के रूप में रू0 77.35 लाख (रूपये सतहत्तर लाख पैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित नियम/शर्तों/प्रतिबन्ध के अधीन संलग्नक के अनुसार सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध</u>

(1) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाईडलाइन्स का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्य एवं मदों हेतु किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 की होगी।

(3) प्रश्नगत धनराशि का व्यय बजट प्राविधान से इतर कार्य/मदों में किया जाना वित्तीय अनियमितता होगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(6) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।

(7) उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(8) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहने का उत्तरदायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 का होगा।

(9) वित्तीय स्वीकृतियॉं जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(10) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(11) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(14) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो, तो संबंधित दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेगें।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाये तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों/नियमों में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी भी प्रकार के विचलन की स्थिति में वे स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

(16) उक्त धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघों को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध आयुक्त को यथासमय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला अधिकारी का होगा।

(17) स्वीकृति धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे बही खाते एवं सम्बिन्धत दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(18) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

(19) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा संबधित दुग्ध संघों को प्रश्नगत कार्यक्रम में उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर शासन को चतुर्थ किश्त की आवश्यकता से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 77,35,000 (रुपये सतहत्तर लाख पैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 016 लेखा शीर्षक 2404001020301 दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश (जिला योजना) मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1- 534 -X-2023-24, दिनांक- 12 फरवरी, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

संख्या- 8/2024/89/003-53-2002-50-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, लखनऊ।
7- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
9- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
11- सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
12- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
13- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।